SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययनः लखनऊ शहर के संदर्भ में

अरविन्द रावत, पीएच–डी., विशेष शिक्षा संकाय,
डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author

अरविन्द रावत, पीएच–डी.

E-mail : rarvind1018@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 15/04/2025
Revised on : 16/06/2025
Accepted on : 25/06/2025
Overall Similarity : 00% on 17/06/2025

शोध सार

आदर्श रूप में समाज के सभी मनुष्यों का समाज में उपलब्ध संसाधनों और अवसरों पर समान पहुँच होना चाहिए परन्तु सामान अधिकारों का वास्तविकता धरातल पर अलग ही है। हमारे देश के अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों एवं शैक्षिक स्थिति अन्य वर्गों से भिन्न है। प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के उन बच्चों जो किसी भी प्रकृति के प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं या अध्ययनरत हैं, के अभिभावकों को जनसंख्या मानते हुए साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर स्व निर्मित उपकरण का प्रयोग कर लखनऊ शहर के अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में आंशिक सुधार अवश्य हुआ है परन्तु आपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। वहीं ये लोग शिक्षा को अनिवार्य मानते हुए इसके प्रति सजग जरूर हुए हैं। जिसका यह परिणाम है कि जो अभिभावक जितना साक्षर है उसके बच्चे उतने अधिक शिक्षित हो रहे हैं?

मुख्य शब्द

अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्र, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति.

प्रस्तावना

आज हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सतत् रूप से प्रगतिशील पथ पर अग्रसर रहते हुए दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल है। ज्ञातव्य है कि हमारा देश विभिन्न समुदायों, धर्मों, वर्गों एवं जातियों के संयुक्त होने से बना

है। जहां प्रत्येक नागरिक को समता एवं समानता के साथ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं परंतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से देश की आबादी का बहुत बड़ा तबका, 21.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीने को बेबस है (तेंदुलकर समिति, 2020 के अनुसार)। मुफलिसी में जीवन जीने वाले ऐसे ही लोग अपनी जीविका की तलाश में गांवों, कस्बों व छोटे छोटे शहरों से महानगरों की ओर पलायन करते हैं जो शहरों एवं महानगरों में अल्पसुविधा प्राप्त क्षेत्रों (मलिन बस्ती) का निर्माण करते हैं या ऐसे क्षेत्रों का अनियोजित विस्तार करते हैं। जिससे इन क्षेत्रों में अधिक भीड़–भाड़ होने से मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता जाता है। हमारे देश में लगभग 6.50 करोड़ लोग (शहरी गरीबी उन्मूलन और आवास मंत्रालय 2011, के अनुसार) अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वहीं मात्र उत्तर प्रदेश में ही लगभग 62.40 लाख लोग इन क्षेत्रों में रहने को मजबूर हैं। अधिसूचित अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों में 5.62 लाख की आबादी, स्वीकृत अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों में 46.78 लाख और चिन्हित अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों में 9.99 लाख की आबादी (भारतीय स्लम जनगणना 2011, के अनुसार) निवास करती है। इन क्षेत्रों में जिस तरह से बेतरतीब जीवन रहा है वह हमारे परिवेश का बहुत ही अफसोस जनक सच है।

एक ओर जहां हमारा देश विकास के पथ पर चलते हुए आधुनिकीकरण और बाजारीकरण में भी तीव्र गति से अग्रसर है जिसकी वजह से बेहतर जीविका, रोजगार और शिक्षा आदि के लिए बड़े शहरों और महानगरों की ओर पलायन ने इसमें और वृद्धि की है जिससे आने वाले समय में जीवन से जुड़ी कई समस्याएं व संकट आ खड़े होंगे। इनमें आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता, बिजली–पानी, परिवहन एवं शिक्षा आदि प्रमुख हैं। ऐसी परिस्थितियां मात्र मेट्रोपोलिटन शहरों में ही उत्पन्न नहीं हो रही बल्कि लखनऊ जैसे छोटे महानगर में भी हो रही है। उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पांचवें स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 19.98 करोड़ (भारतीय जनगणना 2011, के अनुसार) है और साक्षरता 69.72 प्रतिशत है। यह प्रदेश देश के अन्य राज्यों की साक्षरता सूची में 29 वें स्थान पर है जो इस प्रदेश की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था की स्थित को स्वयं ही बयां करती है। इस राज्य की कुल जनसंख्या में अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों (मलिन बस्ती) की भागीदारी 9.5 प्रतिशत जो महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद चौथे स्थान पर है, जबकि 2001 में इस प्रदेश की अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों की जनसँख्या 11 प्रतिशत थी। राज्य के अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के लोगों की साक्षरता दर 69 प्रतिशत (भारतीय स्लम जनगणना 2011, के अनुसार) है जो लगभग राज्य की साक्षरता दर से थोड़ी ही कम है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों (मलिन बस्ती) की आबादी वाले ज़िलों में मेरठ, आगरा, कानपुर नगर के बाद चौथे स्थान पर लखनऊ जिले का नाम आता है। राजधानी लखनऊ में 502 अधिसूचित अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्र हैं और 107 गैर अधिसूचित क्षेत्र हैं। इन दोनों प्रकार के क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 772807 और साक्षरता 75.95 प्रतिशत (लखनऊ सिटी डेवलपमेंट प्लान 2011 के अनुसार) है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों के लोग समाज की मुख्यधारा से पृथक व कमजोर दिखते हैं। आखिर वे कौन से कारण हैं जिससे इन लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। इन लोगों का भविष्य कैसा होगा इसके बारे में मात्र कयास ही लगाए जा सकते हैं। प्रस्तुत शोध लेख में केवल लखनऊ शहर के अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों (मलिन बस्ती) के बच्चों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करेगें।

शुक्ल, (2018) ने कानपुर महानगर की मलिन बस्तियों में जीवन का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन शीर्षक शोध में पाया कि इन क्षेत्रों के 51 प्रतिशत घर घासफूस, गारा और कच्ची ईंटों से बने हैं, यहाँ पेयजल की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत सरकारी नल है, 29 प्रतिशत जनसंख्या को सामुदायिक शौचालय की सुविधा मुहैइय्या है वही 59 प्रतिशत जनसंख्या शौच हेतु आज भी खुले मैदानों का चयन करती है। सीवर सिस्टम के नाम पर खुली हुई नालियां है जो कूड़ा करकट व सफाई के अभाव में जाम हो जाती है। यादव, (2014) ने अपने शोध स्लम एजुकेशन इन इलाहबाद में बताया कि इन क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति दयनीय अवश्य है परन्तु अभिभावकों की शैक्षिक स्तर के स्थिति के अनुसार उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है वहीं सिंह, (2013) एवं चौधरी, (2014) ने पाकिस्तान के लाहौर नगर की मलिन बस्तियों की जीवन शैलियों का अध्ययन करके बताया कि शिक्षा, पानी, स्वच्छता एवं बिजली आदि मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। संवेदना ब्लॉग (2017) में मलिन बस्ती में महिलाओं

की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन में भी बताया गया कि इन क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति अत्याधिक ख़राब है जो पुरुषों की अपेक्षा भी अत्याधिक कम है। धनलक्ष्मी, (2008) ने अपने शोध अध्ययन सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन इन स्लम्स ऑफ ग्रेटर विशाखापट्टनम मुनिसिपल कारपोरेशन ऑफ़ आंध्र प्रदेश में बताया है कि इन क्षेत्रों के 50 प्रतिशत से अधिक अभिभावक निरक्षर हैं जिनमें महिला अभिभावकों का निरक्षरता प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार का अध्ययन झा (1986) और शेख (1983) ने अपने अध्ययन ए स्टडी ऑफ़ लाइफ स्टाइल ऑफ़ स्लम ड्वेलर्स एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन में बताया कि इन क्षेत्रों में अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों से अधिक है और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। माथुर(1987) ने अपने अध्ययन सोशियो इकोनोमिक प्रोफाइल ऑफ़ अर्बन स्लम्स– ए केश स्टडी ऑफ़ जयपुर सिटी स्लम्स, अर्बन डिक्लाइन एंड रेविटेलाईन कांसेप्ट में बताया कि जयपुर की समग्र साक्षरता की तुलना में यहां के झुग्गीवासियों की साक्षरता बहुत कम है। सक्सेना (1986) ने द प्रॉब्लम ऑफ़ स्लम इन स्माल टाउनः द केस स्टडी ऑफ़ श्रीनगर में पाया कि 5 प्रतिशत स्लमवासी ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसी प्रकार धनलक्ष्मी (2008), ने बताया कि व्यवसाय आकस्मिक प्रकृति का होता है और ये दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। वर्मा (1995) ने सोशल वर्क इंटरवेंशन फॉर स्लम इम्प्रोवमेंट अध्ययन में बताया कि इन क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या निर्माण मजदूर, वेंडर, कुली, समाचार पत्र विक्रेता, सड़कों के किनारे दुकाने लगाने वाले, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में कम करते हैं। सिंह (1997) ने अपने अध्ययन ट्रांजिट स्कूल ए न्यू एनिसियेटीव इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड लेबरर्स इन चेन्नई सिटी में बताया कि अनियमित एवं अकुशल कार्य इन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए मजबूर करती है साथ ही इन बस्तियों की महिलाएं अन्य कोई भी काम नहीं करती या फिर नौकरानी के रूप में, सफाई कर्मचारी या सहायक के रूप में ही कार्य करती है।

अध्ययन की आवश्यकता

आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण देश की लगभग 6.50 करोड़ जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) विभिन्न शहरों में अपनी जीविका हेतु अलग अलग क्षेत्रों से पलायन करते हैं ताकि वे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके, परंतु वे अधिकांशतः स्वयं अशिक्षित एवं अकुशल होते हैं जिससे वे विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में असंगठित रूप से कार्य करने को मजबूर होते हैं। ऐसा पूर्व के अध्ययनों व शोधों से प्रतीत होता है कि जहां यादव, धनलक्ष्मी, झा, सक्सेना और माथुर ने इन क्षेत्रों के अभिभावकों के शैक्षिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इनकी शैक्षिक स्थिति बहुत दयनीय है वहीं शुक्ला, सिंह एवं चौधरी, वर्मा, सिंह एवं शेख ने इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करके विभिन्न शहरों के सापेक्ष पाया कि इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत ही प्रतिकूल हैं। उपरोक्त अध्ययनों से ज्ञात होता है कि लखनऊ शहर के अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति जानने का प्रयास नहीं किया गया इसीलिए प्रस्तुत शोध प्रश्न पत्र के माध्यम से शोधार्थी द्वारा लखनऊ शहर के अधिसूचित अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की जननांकीय स्थिति के अंतर्गत सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति जानने का प्रयास किया गया है तथा वे अभिभावक जिनके बच्चे वर्तमान समय में किसी भी प्रकृति के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित या अध्ययनरत हैं। अतः उपरोक्त विषय के उत्तर हेतु निम्नलिखित प्रश्न बनते हैं:

शोध प्रश्न

- अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की जननांकीय स्थिति क्या है?
- अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का क्या है?
- अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति क्या है?

समस्या कथन

अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययनः लखनऊ शहर के संदर्भ में।

शोध उद्देश्य

- अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के बच्चों अभिभावकों की जननांकीय स्थिति का अध्ययन करना।
- अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के बच्चों अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।

संक्रियात्मक परिभाषाएं

1. अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्र की परिभाषा

अस्वस्थकर स्थितियों में पर्याप्त स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं से रहित अधिकतर अस्थाई, कमजोर और सघन रूप से बने कम से कम 20 घरों की स्थाई बस्ती जो लखनऊ नगर निगम द्वारा अधिसूचित हो तथा जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर (गरीबी रेखा से नीचे– बी. पी. एल.) व्यक्ति निवास कर रहे हों द्य

2. अभिभावक से तात्पर्य

उन बच्चों के माता–पिता या संरक्षक जिनके बच्चे वर्तमान समय में किसी भी प्रकृति के प्राथमिक विद्यालय में अध्यनरत् हैं।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर के अधिसूचित 502 अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों (मलिन बस्ती) के वे समस्त अभिभावक जिनके बच्चे इन क्षेत्रों के किसी भी प्रकृति के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित या अध्ययनरत हैं, वर्तमान अध्ययन की जनसंख्या है।

न्यादर्श

लखनऊ शहर के 502 अधिसूचित क्षेत्रों को समग्र मानते हुए क्षेत्र यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर 12 (06 अधिकतम जनसँख्या एवं 06 न्यूनतम जनसँख्या वाले) क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 251 बच्चों के 51 अभिभावकों को साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर चयनित किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु स्व–निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है जिसमें अल्प सुविधा प्राप्त चित्रों के बच्चों के अभिभावकों की जननांकीय स्थिति के अन्तर्गत उनकी वर्तमान सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति जानने हेतु अनुसूची विकसित की गई हैद्य इस अनुसूची में 2 भाग हैं। प्रथम भाग में बच्चों के अभिभावकों से संबंधित सामान्य जानकारी एवं दूसरे भाग में अभिभावक जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ उपलब्ध सुविधाओं व असुविधाओं से संबंधित 17 प्रश्नों को निर्मित किया गया है।

आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण

प्रस्तुत शोध हेतु शोधार्थी ने इन क्षेत्रों के 251 बच्चों के 51 अभिभावकों से साक्षात्कार तकनीकी द्वारा आंकड़ों का संग्रह किया है तथा इसका विश्लेषण ग्राफ के माध्यम से किया गया है।

अभिभावकों की आय का स्रोत

क्रम संख्या	अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता		
	शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
1	हाई स्कूल पास	02	03.9 प्रतिशत
2	उच्च प्राथमिक	01	02.0 प्रतिशत
3	पांचवीं पास	11	21.6 प्रतिशत
4	चौथी पास	01	02.0 प्रतिशत
5	निरक्षर	36	70.6 प्रतिशत

अभिभावकों की आय का स्रोत का बार ग्राफ

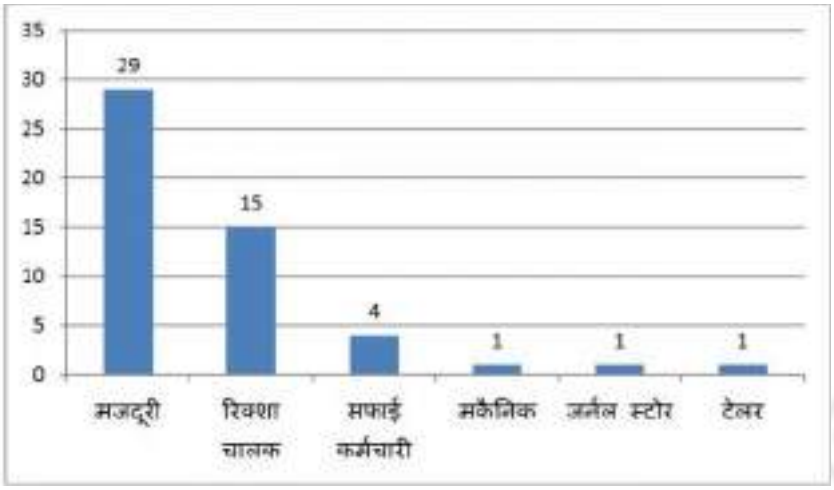

उपरोक्त तालिका अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति से संबंधित है। इन क्षेत्रों के 86.3 प्रतिशत लोग एकल परिवारों के रूप में जबकि मात्र 13.7 प्रतिशत लोग ही संयुक्त परिवार में रहते हैं।

इनमें से अधिकांश लोग दूसरे जिलों व गांवों एवं कस्बों से पलायन कर यहाँ इन क्षेत्रों में रहने लगे हैं।

इन सभी का उद्देश्य अपनी जीविका के लिए कोई रोजगार करना और बच्चों को शिक्षित करना है।

इन क्षेत्रों के परिवारों ने अपनी आजीविका हेतु भिन्न–भिन्न रोजगार अपनाए हुए हैं।

सबसे अधिक 56.9 प्रतिशत अभिभावक दैनिक मजदूर हैं, 29.4 प्रतिशत बैटरी रिक्शा चालक, 47.8 प्रतिशत सफाई कर्मचारी (ठेकेदारों के अंतर्गत), 2 प्रतिशत जनरल स्टोर और दो ही प्रतिशत मैकेनिक एवं ट्रेलर का काम करके अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। इन सभी की मासिक आय लगभग रु. 5000–10000 के बीच ही है।

आजीविका के अन्य संसाधनों के रूप में इनके घरों की महिलाएं दूसरों के घरों में नौकरानी या खाना बनाने या बच्चों को देखभाल करने का काम करती है। मात्र 13.7 प्रतिशत महिलाएं रोजगार करती हैं जबकि 86.3 प्रतिशत महिलाएं कोई रोजगार नहीं करती हैं यह सभी अपने घरों में ही रहकर दिनचर्या पूरा करती है।

अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में प्राप्त सुविधाओं की स्थिति का बारग्राफ

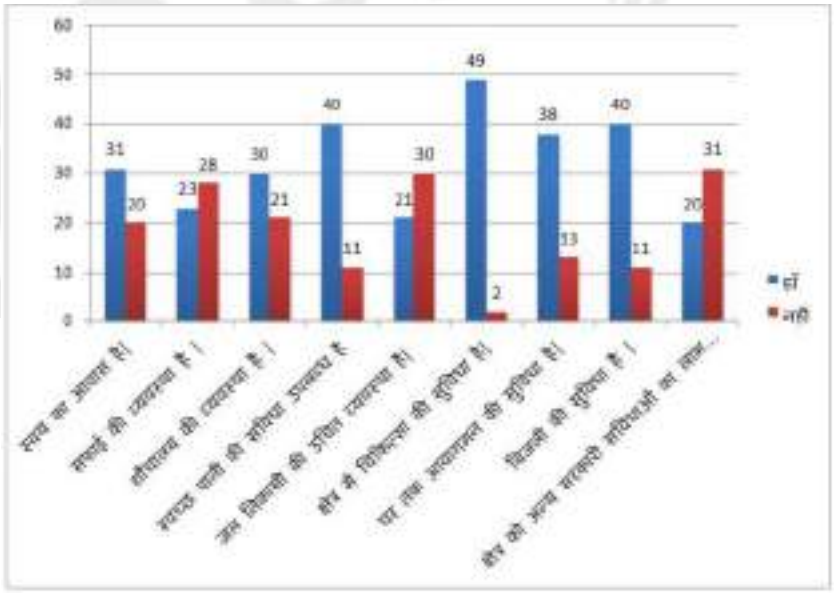

उपरोक्त तालिका में इन क्षेत्रों में प्राप्त सुविधाओं की स्थिति पर भी प्रकाश डालता है जिससे स्पष्ट होता है कि 60.8 प्रतिशत अभिभावकों का स्वयं का आवास है, 54.9 प्रतिशत क्षेत्रों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, 58. 8 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं है, वहीं स्वच्छ पानी की सुविधा 78.4 प्रतिशत क्षेत्रों में है, जल निकासी की उचित व्यवस्था 41.9 प्रतिशत क्षेत्रों में ही है, 96.1 प्रतिशत क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं हैं तो 74.5 प्रतिशत चित्रों में आवागमन की और 78.4 प्रतिशत लोग पास बिजली की सुविधाएं हैं तथा शेष अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मात्र 39.21 प्रतिशत लोगों को होता है।

अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता का बार ग्राफ

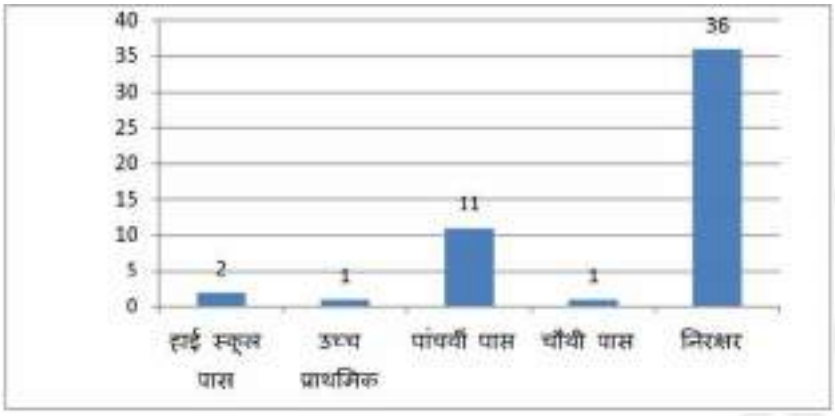

उपरोक्त तालिका द्वारा अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है कि मात्र 2 प्रतिशत अभिभावक चौथी पास, 2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 21.6 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए हैं और 3.65 प्रतिशत ही हाईस्कूल पास है वहीं 70.5 प्रतिशत अभिभावक आज भी निरीक्षर या अनपढ़ है।

निष्कर्ष

राज्य के अल्प सुविधा प्राप्त शहरी क्षेत्रों के लोगों की साक्षरता दर 69 प्रतिशत (भारतीय स्लम जनगणना 2011, के अनुसार) है। राजधानी लखनऊ की साक्षरता 75.95 प्रतिशत (लखनऊ सिटी डेवलपमेंट प्लान, 2011 के अनुसार) है जबकि प्रस्तुत अध्ययन के आंकड़ों के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप ज्ञात होता है कि 70.6 प्रतिशत अभिभावक निरीक्षर या अनपढ़ है जिसमें 21 प्रतिशत अभिभावक प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हैं वहीं 2 प्रतिशत महिला अभिभावक उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए हैं। जो स्लम जनगणना, 2011 एवं लखनऊ सिटी डेवलपमेंट प्लान, 2011 के आंकड़ों के बिलकुल विपरीत स्थिति को दर्शाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में यह जरुर स्पष्ट होता है कि अभिभावकों का शैक्षिक स्तर जैसे–जैसे बढ़ता गया उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि हुई जो अभिभावक अधिक पढ़े–लिखे हैं वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हैं। जिन बच्चों के माता–पिता निरक्षर थे वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कम जागरूक पाए गए पर एक बात संतोष प्रदान करने वाली है कि निरक्षर अभिभावकों का भी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। व्यवसाय के रूप में आज भी सबसे अधिक 56. 52 प्रतिशत लोगों का रोजगार दुकानों या जनरल स्टोर पर काम करके अपनी जीविका चलाना है। महिलाओं की आय की स्थिति और भी खराब है, मात्र 13.7 प्रतिशत महिलाएं ही कोई न कोई कार्य या रोजगार करती है। पिछले तीन दशकों में पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन, बिजली की सुविधाओं में वृद्धि होने से इनकी दैनिक परिस्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हुए है परन्तु आज भी इन क्षेत्रों के अधिकांश लोग अस्थाई आवासों में रहने को मजबूर हैं जिसमें से अधिकांश अनाधिकृत क्षेत्र में ही बने हैं तो स्वाभाविक है जिन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं उसमें से अधिकांश क्षेत्रों में सफाई, शौचालय, जल निकासी व अन्य सरकारी सुविधाओं का अभाव है। अतः इन क्षेत्रों के बच्चों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है परन्तु आपेक्षित सुधार नहीं हुआ है इसलिए अभी भी इस क्षेत्र के लिए कार्य करने वाली सभी सरकारी व गैर सरकारी

संस्थाओं और स्टेक होल्डर्स को नेक इरादों व सकारात्मक इच्छाशक्ति से इन क्षेत्रों के लोंगों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा।

सुझाव

इन क्षेत्रों के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों का मुख्य कारण गरीबी और दूसरा अशिक्षा है। इस बारे में शुक्ल (2018), यादव (2014), चौधरी (2014), सिंह (2013) आदि ने अपने अध्ययनों में बताया है कि यह लोग गरीबी के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं। इसके लिए आजीविका के साधनों की तलाश करने की तत्काल आवश्यकता शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के प्रति जागरूक करना तत्पश्चात इनको यह बताना कि इनकी जीविका शिक्षा प्राप्ति के पश्चात कैसे परिवर्तित हो सकती है, के प्रति प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने कोई प्रयास नही किया। पूर्व सरकारों ने इस क्षेत्र के लिए कार्य किये हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने 28 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री जी ने 'उत्तर प्रदेश स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति, 2021' के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसके अंतर्गत इन क्षेत्रों के लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराये जायेगें। ऐसे ही अनेक नीतियों की जरूरत है जो इन लोगों की शिक्षा एवं रोजगार के लिए हो। सरकार को इन क्षेत्रों के जो लोग अकुशल कारीगर है उन्हें प्रशिक्षित कर कुशल कारीगर बनाकर उनके कौशलों एवं योग्ताओं के अनुसार उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इस कार्य में सरकरों के अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाओं और वे लोग जो ऐसे समाज के लिए चिन्तनशील हैं, उनको भी अपने व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे जिससे इनके बढ़ते पलायन को रोका जा सके। उनके गांवों एवं कस्बों में या नजदीक ही सक्षम रोजगार के नए अवसर सृजित करना होगा जिससे इन्हें अपने क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान निरंतर चलाने के साथ–साथ इनके बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष प्रबंधन के कार्यक्रम और विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन सभी प्रक्रियाओं पर निगरानी के लिए एक समिति गठित होनी चाहिए जिसमें शासन– प्रशासन के अतिरिक्त सामाजिक कार्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को शामिल करना होगा जो समय समय पर इन क्षेत्रों में हुए उन्नतियों और औन्तियों पर सतत् ध्यान दे अर्थात् उनके कार्यों का मूल्यांकन करें जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोग सकारात्मक सुधार हेतु प्रयत्नशील एवं सचेत रहे। शासन– प्रशासन को भी इस ओर अधिक ध्यान देते हुए अपनी विशेष हस्तक्षेप की नीति का पालन करना होगा। तभी इन क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में आपेक्षित सुधार संभव हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. धनलक्ष्मी, एम. (2008) *सिचुएसनल एनालिसिस ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन इन स्लम्स ऑफ़ ग्रेटर,* विशाखापत्तनम मुनिसिपल कारपोरेशन ऑफ़ आँध्रप्रदेश।
2. माथुर, एच.एस. (1987) *सोसिओ इकोनोमिक प्रोफ़ाइल ऑफ़ अर्बन स्लम्स – ए केस स्टडी ऑफ़ जयपुर सिटी स्लम्स.अर्बन डिक्लाइन एंड रेविटेलाईन,* कांसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 07।
3. मोहसिन, एन.(1980) फॉर स्लम्स चिल्ड्रेन स्कूलिंग इज ए लक्जरी, *सोशल वेलफेयर,* 27(2), अप्रैल– मई, 25–27।
4. एन. डी. (29 अक्टुबर, 2021) उत्तर प्रदेश स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति, 2021, drishtiias.com/hindi/state-pcs-current-affairs/uttar pradesh.in-slum-redevelopment-2021, Retrieved from 15-08-2023
5. एन. डी.(13 जून, 2017) मलिन बस्ती में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययने, amvedanaa.blogspot.com/2017/06/status-of-women-education-in-slums-in.html, Retrieved from 15-08-2023
6. ओझा, एस. के. (2018) जनसँख्या एवं नगरीकरण, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, 65–66।

7. शेख, आर. ए. (1983) ए स्टडी ऑफ़ लाइफ स्टाइल ऑफ़ स्लम्स ड्वेलर्स एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन. पी–एच. डी., एजुकेशन रिसर्च इन दी एजुकेशन ऑफ़ दी डिस एडवांसज दृ ए ट्रेड रिपोर्ट, फोर्थ सर्वे ऑफ़ रिसर्च इन एजुकेशन, एम. बी. बुच (ईडी) एन. सी. ई. आर. टी. 02, 1983–88, 1424.

8. सक्सेना, एच. एम. (1986) दी प्रॉब्लम ऑफ़ स्लम्स इन स्माल टाउन्सः दी केस स्टडी ऑफ़ श्रृंगारनगरए *कांसेप्ट इंटरनेशनल सीरीज इन जियोग्राफी, पर्सपेक्टिव इन अर्बन जियोग्राफी,* 7(3)1986, 253–257।

9. सेन्सस ऑफ़ इंडिया 2011, http://www.2011.co.in/slums.php, Retrieved from 14-07-2021

10. सेन्सस ऑफ़ इंडिया 2011, http://www.2011.co.in/slums.php, Retrieved from 31-07-2021

11. सेन्सस ऑफ़ इंडिया 2011, http:.//www.censusindia.2001.gov.in/DataHighlight/metadata-highlightspdf, Retrieved from 09-05-2020

12. सिंह, ए. (1997) *एडोल्सेंस गर्ल्स इन स्लम्स,* अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली।

13. सिंह, पी. (22 दिसम्बर, 2012) इस शहर का क्या करें? *जनसत्ता,* रविवार, इण्डिया पवार पोर्टल (हिंदी), http://indiawaterportal/hindi, Retrieved from 15-06-2021

14. शुक्ल,आर. (2018) कानपुर महानगर की मलिन बस्तियों में जीवन का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन, https:/ /journal.ijarms.org/index.php/ijarms/article/view/8, Retrieved from 14-08-2023

15. तेदुलकर समिति (2020,अक्टूबर 27) गरीबी मापने का आधार, http://www.drishtiias.com>hindi, Retrieved from 30-07-2023.

16. यादव, वी. के. (2014) स्लम एजुकेशन इन इलाहबाद. http://www.slumeducation.com, Retrieved from 15-08-2021

17. वर्मा, आर. बी. एस. (1997) सोशल वर्क इंटरवेंसन फॉर स्लम्स एम्प्रोव्मेंट, कांटेम्पोरेरी सोशल वर्क, 14, अक्टूबर 1997, 321।

****